मंगलवार, 21 अप्रैल, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

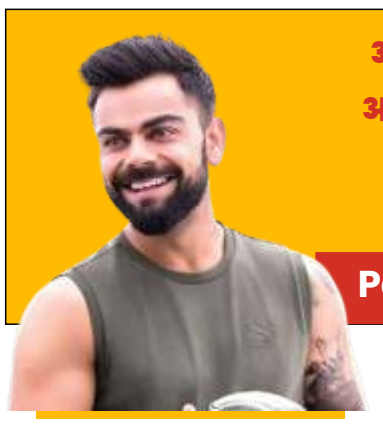

अक्षय तृतिया पर अनुष्का शर्मा संग पहुंचे कोहली

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

जेस्मिन सैंडलस का बड़ा खुलासा: शराब की लत से जंग की दर्दनाक कहानी

Page-05

विस्फोट इतना तेज था कि आसपास के हिस्सों में भी कंपन महसूस किया गया। मौके पर मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया और तत्काल आपातकालीन प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया।

बालोतरा रिफाइनरी में भीषण आग

पीएम मोदी का दौरा स्थगित

- **रिफाइनरी में विस्फोट के बाद लगी आग पर करीब 2 घंटे में काबू पाया गया, कोई हताहत नहीं।**
- **हादसे के चलते प्रधानमंत्री का प्रस्तावित लोकार्पण कार्यक्रम फिलहाल स्थगित।**

राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा स्थित रिफाइनरी प्लांट में सोमवार दोपहर अचानक भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। यह हादसा उस समय हुआ जब एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में थीं। घटना के बाद सुरक्षा कारणों से उनका दौरा स्थगित कर दिया गया है।जानकारी के अनुसार, दोपहर करीब 2 बजे रिफाइनरी के CDU-VDU सेक्शन में एक एक्सचेंजर में विस्फोट हो गया, जिससे आग तेजी से फैल गई। विस्फोट इतना तेज था कि आसपास के हिस्सों में भी कंपन महसूस किया गया। मौके पर मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया और तत्काल आपातकालीन प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया। हालात को देखते हुए पूरे प्लांट क्षेत्र को खाली करा लिया गया और सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।आग की सूचना मिलते ही प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं। बड़ी संख्या में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर पहले से तैनात दमकल वाहन भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए, जिससे राहत कार्य में तेजी आई। करीब एक दर्जन दमकलकर्मियों ने लगातार प्रयास कर लगभग दो घंटे में आग पर काबू पा लिया। फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।इस घटना पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि पचपदरा रिफाइनरी राज्य के लिए गर्व की परियोजना है और उद्घाटन से ठीक पहले इस तरह की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने वहां मौजूद सभी कर्मचारियों की सुरक्षा की कामना की।

नागरिकता के प्रस्ताव ठुकराकर चर्चा में राशिद खान

अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग में गुजरात टाइटन्स के लिए खेल रहे हैं, लेकिन अपनी आगामी किताब Rashid Khan: From Streets to Stardom को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। इस किताब में उन्होंने अपने करियर और निजी जीवन से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।राशिद खान ने दावा किया है कि पिछले कुछ वर्षों में उन्हें भारत और ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता अपनाने के प्रस्ताव मिले थे, जिन्हें उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव अनौपचारिक रूप से दिए गए थे, लेकिन काफी गंभीर थे।किताब के अनुसार, आईपीएल 2023 के दौरान उनसे संपर्क किया गया था। राशिद ने खुलासा किया कि एक वरिष्ठ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अधिकारी ने उनसे बातचीत की और अफगानिस्तान की परिस्थितियों का हवाला देते हुए उन्हें भारतीय नागरिकता अपनाने का सुझाव दिया।हालांकि, राशिद खान ने साफ किया कि उन्होंने अपने देश अफगानिस्तान के प्रति निष्ठा को प्राथमिकता दी और किसी भी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनका यह फैसला उनके देशप्रेम और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।राशिद की यह किताब जल्द ही प्रकाशित होने वाली है, जिसमें उनके संघर्ष, करियर और ऐसे कई अहम अनुभवों का जिक्र किया गया है, जो उनके प्रशंसकों के लिए बेहद दिलचस्प साबित हो सकते हैं।

राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले से जज सुभाष विद्यार्थी अलग

कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े कथित दोहरी नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अहम घटनाक्रम सामने आया है। इस केस की सुनवाई कर रहे जज सुभाष विद्यार्थी ने खुद को मामले से अलग कर लिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने यह निर्णय याचिकाकर्ता की सोशल मीडिया पोस्ट से नाराज होकर लिया।दरअसल, याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट साझा करते हुए चेतावनी दी थी कि यदि किसी ने पैसा लिया है तो उसे वापस कर दे, अन्यथा जेल जाना होगा। हालांकि, इस पोस्ट में किसी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया था, लेकिन इसे अदालत की कार्यवाही से जोड़कर देखा गया।इससे पहले 17 अप्रैल को जज सुभाष विद्यार्थी ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराने का आदेश दिया था। हालांकि, अगले ही दिन उन्होंने अपना आदेश संशोधित करते हुए कहा कि बिना नोटिस दिए ऐसा फैसला उचित नहीं है।

दिल्ली में महंगी हो सकती है बिजली

30 हजार करोड़ बकाया पर APTEL के फैसले से बढ़े टैरिफ के संकेत

दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं के लिए आने वाले महीनों में राहत की बजाय आर्थिक दबाव बढ़ने की आशंका है। अपीलीय बिजली ट्रिब्यूनल (APTEL) ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें करीब 30,000 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया था। इस फैसले के बाद अब राजधानी में बिजली दरों में बढ़ोतरी की संभावना काफी मजबूत मानी जा रही है।यह पूरा मामला बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लंबे समय से लंबित बकाया से जुड़ा है। ये बकाया "रेगुलेटरी एसेट्स" के रूप में जमा होते गए, क्योंकि बीते वर्षों में बिजली दरें कम रखी गईं, जबकि लागत लगातार बढ़ती रही।DERC ने ट्रिब्यूनल से दलील दी थी कि यदि भुगतान की समयसीमा बढ़ा दी जाए, तो उपभोक्ताओं पर अचानक बोझ नहीं पड़ेगा और दरों में तेज बढ़ोतरी से बचा जा सकेगा। हालांकि, APTEL ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और पहले से तय भुगतान समयसीमा को लागू रखने का निर्देश दिया।दरअसल, यह विवाद सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2025 के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें सभी राज्यों को निर्देश दिया गया था कि वे अप्रैल 2024 से लेकर 2028 तक बिजली क्षेत्र के पुराने बकायों का निपटान करें। साथ ही जरूरत पड़ने पर टैरिफ बढ़ाने की अनुमति भी दी गई थी।दिल्ली की स्थिति अन्य राज्यों से अलग है, क्योंकि यहां बिजली वितरण कंपनियां निजी हैं। ऐसे में सरकार के लिए पूरे बोझ को खुद उठाना आसान नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि बकाया वसूली या तो बिजली दरों में बढ़ोतरी, सरकारी सब्सिडी, या दोनों के मिश्रण से की जा सकती है। कुल मिलाकर, जब तक कोई वैकल्पिक वित्तीय समाधान नहीं निकलता, दिल्ली के घरों और व्यवसायों को आने वाले समय में बढ़े हुए बिजली बिल का सामना करना पड़ सकता है।

हिन्दी जगत महामंच

www.tvbharatvarsh.in

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक ई-पेपर

प्रदेश का नं. 1 प्रतिष्ठित हिन्दी न्यूज़ ई-पेपर

विज्ञापन दर

साईज	विजिटिंग कार्ड	क्वाटर पेज	हाफ पेज	फुल पेज (अंदर)	फुल पेज (कवर 2 - 3)	फुल पेज (कवर 4 - अंतिम)	(फ्रंट पेज)
रेट	₹ 3000	₹ 6000	₹ 10,000	₹ 20,000	₹ 25,000	₹ 30,000	₹ 100000

8601780000

उधमपुर में दर्दनाक बस हादसा

खाई में गिरने से 21 की मौत, 29 घायल

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में सोमवार सुबह एक भयावह सड़क हादसा सामने आया, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। रामनगर क्षेत्र में एक तेज रफ्तार निजी बस अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में अब तक 21 यात्रियों की मौत हो चुकी है, जबकि 29 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।प्रत्यक्षदर्शियों और अधिकारियों के अनुसार, हादसा सुबह करीब 10 बजे एक खतरनाक मोड़ पर हुआ, जहां चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा। बस की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके कारण वह संतुलन नहीं बना सकी और सीधे खाई में जा गिरी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बस का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और वाहन मलबे में तब्दील हो गया।बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान बस ने एक ऑटो-रिक्शा को भी टक्कर मार दी, जिससे उसमें सवार लोग भी घायल हो गए। दुर्घटना के समय बस में लगभग 50 यात्री सवार थे, जिनमें अधिकतर लोग रोजमर्रा के काम के लिए रामनगर से उधमपुर की ओर जा रहे थे।घटना के तुरंत बाद पास से गुजर रहे सेना के काफिले ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और बचाव दल भी मौके पर पहुंच गए और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं और मृतकों के परिजनों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है।

अब सीमाओं में नहीं बंधेगा भारत

रूस के ठिकानों से करेगा ऑपरेशन

भारत और रूस के बीच RELOS समझौते से दोनों देश एक-दूसरे के सैन्य ठिकानों का उपयोग कर सकेंगे। इससे भारत की वैश्विक सैन्य पहुंच, लॉजिस्टिक क्षमता और रणनीतिक स्वायत्तता मजबूत होगी। चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच यह कदम संतुलित कूटनीति का संकेत देता है।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक समझौता पूरी तरह लागू हो गया है, जिसने वैश्विक स्तर पर नई बहस को जन्म दिया है। "रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट" (RELOS) नामक इस समझौते के तहत दोनों देश अब एक-दूसरे के सैन्य ठिकानों—एयरबेस, नौसैनिक अड्डों और अन्य लॉजिस्टिक सुविधाओं—का उपयोग कर सकेंगे। यह कदम ऐसे समय में सामने आया है जब दुनिया तेजी से बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों के दौर से गुजर रही है।इस समझौते के तहत भारत और रूस एक-दूसरे के क्षेत्र में अपने सैन्य संसाधनों की तैनाती कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों देश एक साथ लगभग 3000 सैनिक, 10 सैन्य विमान और 5 युद्धपोत तक तैनात करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि, इस समझौते की असली ताकत केवल तैनाती तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तहत मिलने वाली व्यापक लॉजिस्टिक सहायता है। इसमें ईंधन आपूर्ति, मरम्मत, रखरखाव, चिकित्सा सहायता और परिवहन जैसी सुविधाएं शामिल हैं, जो किसी भी सैन्य अभियान को लंबे समय तक और प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद करती हैं। इस समझौते से भारत की सैन्य पहुंच और परिचालन क्षमता में बड़ा विस्तार होगा। अब भारतीय सशस्त्र बल केवल अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में तेजी से तैनात होकर ऑपरेशन चला सकेंगे। यह भारत की रक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जो उसे एक क्षेत्रीय शक्ति से आगे बढ़ाकर वैश्विक स्तर पर सक्रिय खिलाड़ी बनने की दिशा में ले जाता है।इस समझौते के पीछे कई रणनीतिक कारण हैं। पहला, वैश्विक शक्ति संतुलन में तेजी से बदलाव हो रहा है, जहां देश अपने-अपने सैन्य नेटवर्क और सप्लाई चेन को मजबूत करने में लगे हैं। दूसरा, चीन का बढ़ता प्रभाव, खासकर एशिया और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में, भारत के लिए चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में भारत के लिए अपनी रणनीतिक पहुंच बढ़ाना आवश्यक हो गया था। तीसरा, पश्चिमी देशों के दबाव के बीच रूस को एक भरोसेमंद साझेदार की जरूरत थी, और भारत इस भूमिका में स्वाभाविक रूप से फिट बैठता है। इस डील का एक बड़ा लाभ भारत को "ग्लोबल रीच" के रूप में मिल सकता है। रूस के पास आर्कटिक से लेकर यूरोप तक फैले कई रणनीतिक सैन्य अड्डे हैं। इस समझौते के बाद भारत को इन क्षेत्रों में पहुंच मिल सकती है, खासकर आर्कटिक क्षेत्र में, जहां भविष्य में नए समुद्री मार्ग और ऊर्जा संसाधनों के अवसर उभर रहे हैं। यह न केवल सैन्य बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, यह समझौता भारत की "स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी" नीति को और मजबूत करता है। भारत पहले ही अमेरिका के साथ LEMOA (Logistics Exchange Memorandum of Agreement) जैसे समझौते कर चुका है। अब रूस के साथ RELOS समझौता यह स्पष्ट करता है कि भारत किसी एक गुट में शामिल होने के बजाय संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति अपना रहा है।

ट्रंप के लिए कितने भरोसेमंद हैं मुनीर

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल हैं, हाल ही में ऐसे पहले विदेशी नेता बने जिन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बाद ईरान का दौरा किया। उनका यह दौरा तीन दिनों तक चला, जिसमें उन्होंने ईरान के शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के साथ अहम बैठकें कीं।रिपोर्ट्स के अनुसार, मुनीर के अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ करीबी संबंध रहे हैं, वहीं ईरान के सैन्य और खुफिया तंत्र के साथ भी उनके मजबूत व्यक्तिगत संपर्क बताए जाते हैं। बताया जाता है कि 2016-17 के दौरान, जब मुनीर पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल थे, उसी समय उन्होंने ईरान के साथ अपने संबंधों की नींव रखी थी। हालांकि, इन रिश्तों को लेकर अमेरिका में चिंता भी जताई जा रही है। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज़ के वरिष्ठ फेलो बिल रोगियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन को पाकिस्तान पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने मुनीर के IRGC से संबंधों को "रेड फ्लैग" बताते हुए चेतावनी दी कि अतीत में अफगानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान का रवैया संदिग्ध रहा है।वहीं, पाकिस्तानी विश्लेषक रज़ा रूमी का मानना है कि मुनीर जैसे सैन्य अधिकारियों का बढ़ता प्रभाव इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान में सेना लगातार नागरिक सरकार पर हावी होती जा रही है।ईरान दौरे के दौरान मुनीर ने देश के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, संसद अध्यक्ष और सैन्य कमान के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। पाकिस्तान सेना के अनुसार, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय शांति प्रयासों को मजबूत करना और संभावित समझौतों को आगे बढ़ाना था।यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है, और ऐसे में मुनीर की यह पहल क्षेत्रीय कूटनीति में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

राजनाथ सिंह का जर्मनी दौरा, रक्षा सहयोग पर फोकस

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 अप्रैल से शुरू होने वाले तीन दिवसीय दौरे पर जर्मनी जाएंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को नई गति देना है। इस दौरे के दौरान वे अपने जर्मन समकक्ष बोरिस पिस्टोरियस और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठकें करेंगे। पिछले सात वर्षों में यह पहला मौका होगा जब कोई भारतीय रक्षा मंत्री जर्मनी का दौरा कर रहा है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह यात्रा भारत और जर्मनी के बीच रक्षा उद्योगों में चल रहे सहयोग की समीक्षा करने और नए अवसरों की तलाश के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बातचीत में रक्षा औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करने, सैन्य-से-सैन्य संबंधों को बढ़ाने और उभरती तकनीकों जैसे साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और ड्रोन क्षेत्र में सहयोग को विस्तार देने पर विशेष ध्यान रहेगा।इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच एक रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के प्रशिक्षण में सहयोग से जुड़ी कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। यह समझौता भविष्य में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा।सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में भारतीय नौसेना के लिए छह उन्नत पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण से जुड़ा प्रोजेक्ट 75। सौदा शामिल है। इस डील की अनुमानित लागत 70,000 करोड़ रुपये से 99,000 करोड़ रुपये के बीच बताई जा रही है। इन पनडुब्बियों का निर्माण मुंबई स्थित मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा जर्मन कंपनी थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स के सहयोग से किया जाएगा।

जहाजों की आवाजाही प्रभावित, सप्लाई पर मंडराया संकट

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

वैश्विक ऊर्जा बाजार एक बार फिर गंभीर अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव और टैंकरों की आवाजाही प्रभावित होने से कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया है। रविवार को शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में कारोबार शुरू होते ही अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत 6.4 प्रतिशत बढ़कर 87.88 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई, जबकि अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 6.5 प्रतिशत उछलकर 96.25 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।इस तेजी की मुख्य वजह ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव है, जिसने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक हॉर्मुज जलडमरूमध्य को प्रभावित किया है। यह जलमार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा वहन करता है, ऐसे में यहां किसी भी तरह का व्यवधान सीधे बाजार को प्रभावित करता है। बाजार में उतार-चढ़ाव पिछले कुछ दिनों से जारी है। शुक्रवार को ईरान ने संकेत दिया था कि वह अपने तट के पास से वाणिज्यिक जहाजों के लिए मार्ग खोल देगा, जिससे तेल कीमतों में 9 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई थी। हालांकि, अगले ही दिन स्थिति बदल गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी जारी रखने की बात कही, जिसके बाद तेहरान ने अपना रुख सख्त कर लिया।

हॉर्मुज जलडमरूमध्य में बड़ा फैसला, चीनी जहाज को नहीं मिली एंट्री

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

मध्य पूर्व के सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण जलमार्ग हॉर्मुज जलडमरूमध्य में हाल ही में घटी एक घटना ने अंतरराष्ट्रीय शिपिंग और भू-राजनीतिक समीकरणों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। एक चीनी स्वामित्व वाले और पूरी तरह चीनी क्रू से संचालित बल्क कैरियर "सन प्रॉफिट" को इस जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद उसे अपना रास्ता बदलकर वापस लौटना पड़ा।इस घटना ने इसलिए अधिक ध्यान आकर्षित किया क्योंकि आम धारणा रही है कि ईरान और चीन के बीच मजबूत रणनीतिक और आर्थिक संबंध हैं। ऐसे में यह माना जाता रहा है कि ईरान चीनी जहाजों को प्राथमिकता देता है। हालांकि, ताजा घटनाक्रम ने इस धारणा को चुनौती दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, "सन प्रॉफिट" जब हॉर्मुज जलडमरूमध्य के पास पहुंचा, तो उसे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। सुरक्षा हालात को देखते हुए जहाज को तत्काल रूट बदलने और वापस लौटने का निर्देश दिया गया। यह कदम दर्शाता है कि ईरान इस संवेदनशील समुद्री मार्ग में किसी भी जहाज को स्वचालित छूट नहीं दे रहा है, बल्कि हर मामले का मूल्यांकन परिस्थितियों के आधार पर किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया भारत स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास की ओर से भी आई। बयान में स्पष्ट किया गया कि ईरान किसी भी देश के साथ पक्षपात नहीं करता और सभी जहाजों के लिए समान नियम लागू हैं। यह संदेश न केवल भारत बल्कि वैश्विक समुदाय को भी दिया गया कि वर्तमान परिस्थितियों में सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। गौरतलब है कि हाल के दिनों में अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके परिणामस्वरूप ईरान ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य में निगरानी और नियंत्रण कड़ा कर दिया है। कुछ स्थानों पर जहाजों को रोके जाने और फायरिंग की घटनाएं भी सामने आई हैं। इसी संदर्भ में भारतीय जहाजों की स्थिति भी उल्लेखनीय रही है। जहां कुछ भारतीय जहाजों को वापस लौटना पड़ा, वहीं कई जहाज जोखिम के बावजूद इस मार्ग से सफलतापूर्वक गुजरने में कामयाब रहे। इससे यह स्पष्ट होता है कि ईरान का निर्णय किसी विशेष देश

संपादक की कलम से

आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में शिक्षा को प्रायः केवल नौकरी प्राप्त करने का माध्यम समझ लिया गया है। अंक, डिग्री और करियर की दौड़ में हम यह भूलते जा रहे हैं कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान का निर्माण भी है। ऐसे में शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों का समावेश अत्यंत आवश्यक हो जाता है। नैतिक मूल्य जैसे ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सहानुभूति और अनुशासन व्यक्ति के चरित्र की नींव होते हैं। ये मूल्य न केवल व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। यदि शिक्षा में इन मूल्यों की अनदेखी की जाती है, तो हम ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करेंगे जो भले ही बुद्धिमान हों, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति उदासीन रहेंगे।आज हम समाज में कई समस्याएँ देख रहे हैं—भ्रष्टाचार, हिंसा, असहिष्णुता और नैतिक पतन। इन समस्याओं का एक प्रमुख कारण शिक्षा में नैतिकता की कमी भी है। जब छात्रों को केवल प्रतिस्पर्धा और सफलता पर ध्यान केंद्रित करना सिखाया जाता है, तो वे सही और गलत के बीच अंतर को नजरअंदाज करने लगते हैं। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षा प्रणाली में नैतिक शिक्षा को समान महत्व दिया जाए। परिवार और विद्यालय दोनों ही इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता-पिता बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं, और उनके व्यवहार से ही बच्चे सीखते हैं। वहीं विद्यालयों में शिक्षकों का दायित्व है कि वे विद्यार्थियों को न केवल पाठ्यक्रम की जानकारी दें, बल्कि उन्हें जीवन के मूल्यों से भी परिचित कराएँ। इसके अलावा, पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों और गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए, जो विद्यार्थियों में सामाजिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता को विकसित करें। समूह कार्य, सामाजिक सेवा और नैतिक कहानियों के माध्यम से इन मूल्यों को व्यवहारिक रूप में सिखाया जा सकता है। अंततः, यह स्पष्ट है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल सफल पेशेवर तैयार करना नहीं, बल्कि जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनाना भी है। जब शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश होगा, तभी हम एक बेहतर समाज और उज्जवल भविष्य की नींव रख पाएँगे।

एम. के. स्टालिन का BJP पर बड़ा हमला, IT रेड को बताया साजिश

तमिलनाडु में एम. के. स्टालिन ने भारतीय जनता पार्टी पर आयकर कार्रवाई के जरिए विपक्ष को दबाने का आरोप लगाया। के. सेल्वपेरुंथगई ने खुद को नजरबंद करने का दावा किया। चुनाव से पहले इस मुद्दे पर सियासी तनाव तेज हो गया है।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

तमिलनाडु की राजनीति में चुनावी माहौल के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को दबाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि आयकर विभाग की हालिया कार्रवाई इसी रणनीति का हिस्सा है।स्टालिन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (टीएनसीसी) के अध्यक्ष के. सेल्वपेरुंथगई के आवास पर हुई कार्रवाई की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे "षड्यंत्र" करार देते हुए कहा कि चुनाव प्रचार खत्म होने में केवल 48 घंटे शेष हैं और ऐसे समय में इस तरह की कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। स्टालिन ने आरोप लगाया कि भाजपा संभावित हार के डर से इस प्रकार के कदम उठा रही है और राज्य की जनता इसका जवाब देगी। इससे पहले के. सेल्वपेरुंथगई ने भी आयकर विभाग पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना है कि अधिकारियों ने उनके आवास पर छापा मारने के साथ-साथ उन्हें प्रभावी रूप से "नजरबंद" कर दिया, जिससे वे अपने चुनावी कार्यक्रमों में भाग नहीं ले सके। उन्होंने दावा किया कि उन्हें श्रीपेरुम्बुदुर विधानसभा क्षेत्र में अपने राजनीतिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका गया।सेल्वपेरुंथगई ने यह भी आरोप लगाया कि उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में आयकर विभाग के अधिकारी तैनात थे, जिनमें से कई हिंदी भाषी थे और स्थानीय भाषा तमिल से परिचित नहीं थे। उनका कहना है कि इन अधिकारियों की मौजूदगी के कारण वे न तो लोगों से मिल पाए और न ही चुनावी गतिविधियों का समन्वय कर सके। उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को "राजनीतिक रूप से प्रेरित" बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने आगे कहा कि यह कार्रवाई केवल उनके तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके मित्रों, रिश्तेदारों और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम से जुड़े पदाधिकारी पद्दई मनोगर के आवासों पर भी तलाशी ली गई। उनके अनुसार, यह व्यापक स्तर पर विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश का संकेत है। सेल्वपेरुंथगई ने भाजपा के साथ-साथ अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पर भी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास है और इससे निष्पक्ष चुनाव पर सवाल उठते हैं। तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पहले ही सियासी माहौल गर्म है, और इस विवाद ने राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप को और तेज कर दिया है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा चुनावी बहस का केंद्र बन सकता है।

असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, विभाजन के लिए कांग्रेस को भी ठहराया जिम्मेदार

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को एक जनसभा में कहा कि 1947 के विभाजन के लिए केवल मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराना गलत है और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी भूमिका रही है। गुजरात के लिंबायत में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने इस मुद्दे पर ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए अपनी बात रखी।उन्होंने देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम का हवाला देते हुए कहा कि आजाद ने उस समय महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से देश के विभाजन को रोकने की अपील की थी। ओवैसी के अनुसार, यह ऐतिहासिक तथ्य दर्शाता है कि विभाजन एक जटिल प्रक्रिया थी, जिसे केवल एक समुदाय पर थोपना सही नहीं है।ओवैसी ने यह भी कहा कि विभाजन के लिए मुसलमानों को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस पार्टी उस समय के निर्णयों के लिए जिम्मेदार नहीं थी। उनके इस बयान ने राजनीतिक बहस को एक बार फिर तेज कर दिया है। इसके अलावा, ओवैसी ने अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पश्चिम बंगाल में भाजपा की "बी टीम" कहे जाने पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि उनकी पार्टी केवल 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दल सैकड़ों सीटों पर मैदान में हैं। उन्होंने विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि वे वास्तव में भाजपा को हराना चाहते हैं, तो उन्हें 270 से अधिक सीटें जीतकर दिखानी चाहिए। ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ दल एक खास समुदाय को अपना नेतृत्व चुनने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी के इस बयान ने आगामी चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया है, जहां विभिन्न दल एक-दूसरे पर तीखे आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं।

डीएमके गठबंधन की जीत का दावा, भाजपा के लिए 'दरवाजे बंद': पी. चिदंबरम

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के नेतृत्व वाला गठबंधन स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगा। एक विशेष संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी के लिए "द्वार पूरी तरह बंद" हैं और तमिलनाडु की जनता भाजपा को कभी स्वीकार नहीं करेगी। चिदंबरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की राज्य में लोकप्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब इन शीर्ष नेताओं की ही साख नहीं है, तो एडप्पाडी के. पलानीस्वामी की भी कोई विशेष पकड़ नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम नेतृत्व भाजपा के सहारे राजनीति कर रहा है, लेकिन जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी।गठबंधन के पिछले प्रदर्शन का हवाला देते हुए चिदंबरम ने कहा कि डीएमके के नेतृत्व वाला मोर्चा लगातार चुनावों में सफल रहा है। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव, 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली जीतों का जिक्र करते हुए कहा कि यह गठबंधन "आजमाया हुआ और भरोसेमंद" है। उन्होंने दावा किया कि 234 सदस्यीय विधानसभा में गठबंधन अधिकतम सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहा है और आराम से बहुमत हासिल करेगा। महिला आरक्षण को लेकर एआईएडीएमके द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए चिदंबरम ने इसे "पूरी तरह झूठ" करार दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण पहले ही संविधान का हिस्सा बन चुका है, जिसे 2023 में संसद द्वारा पारित 106वें संविधान संशोधन के जरिए लागू किया गया। उन्होंने विपक्षी नेताओं को सलाह दी कि वे तथ्यों की जानकारी लें और भ्रामक बयानबाजी से बचें। इस दौरान चिदंबरम ने राहुल गांधी के उस बयान का भी समर्थन किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तमिलनाडु में "घुसपैठ" की कोशिश कर रहे हैं। चिदंबरम ने कहा कि पिछले एक दशक से उनकी पार्टी यह मुद्दा उठा रही है और राज्य की जनता ने भाजपा को लगातार नकारा है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने हाल ही में एक रैली में आरोप लगाया था कि भाजपा का उद्देश्य मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन को हटाकर किसी "कठपुतली सरकार" को स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की भाषा, संस्कृति और परंपरा पर किसी भी प्रकार का हमला राज्य की जनता स्वीकार नहीं करेगी।

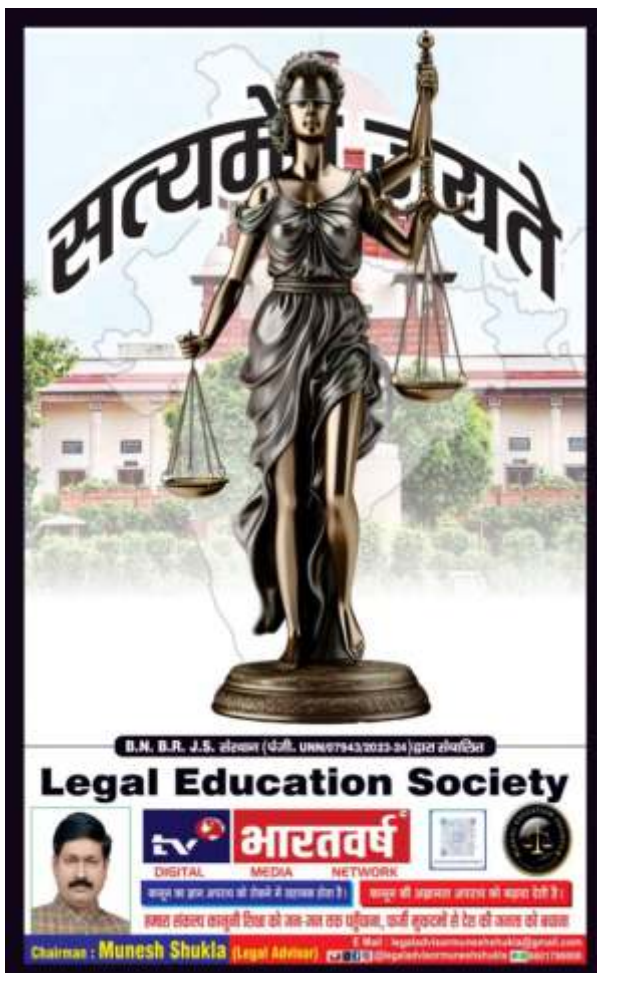

बाजार में तेजी का धमाका!

टॉप 10 में से 8 कंपनियों की वैल्यू में ₹1.87 लाख करोड़ का उछाल

भारतीय शेयर बाजार में बीते सप्ताह मजबूत तेजी देखने को मिली, जिसका असर देश की शीर्ष कंपनियों के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) पर भी साफ दिखाई दिया। मार्केट कैप के लिहाज से देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 8 की कुल वैल्यू में लगभग 1.87 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई। इस उछाल में सबसे अधिक योगदान भारती एयरटेल का रहा, जिसकी बाजार पूंजीकरण में 58,831 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई और यह बढ़कर 11.25 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसी तरह भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की मार्केट वैल्यू 27,608 करोड़ रुपये बढ़कर 5.32 लाख करोड़ रुपये हो गई। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी वैल्यू 20,731 करोड़ रुपये बढ़कर 9.34 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टुब्रो, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंफोसिस जैसी कंपनियों की वैल्यू में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई।हालांकि, सभी कंपनियों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक नहीं रहा। एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 16,163 करोड़ रुपये घटकर 12.31 लाख करोड़ रुपये रह गया, जबकि बजाज फाइनेंस की वैल्यू 9,769 करोड़ रुपये गिरकर 5.65 लाख करोड़ रुपये पर आ गई। शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में भी तेजी देखी गई। बीएसई सेंसेक्स बीते सप्ताह 943.29 अंक यानी 1.21 प्रतिशत चढ़ा, जबकि निफ्टी 50 में 302.95 अंक यानी 1.25 प्रतिशत की बढ़त रही। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन शुक्रवार को सेंसेक्स 505 अंक (0.65%) की बढ़त के साथ 78,494 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 157 अंक (0.65%) चढ़कर 24,354 पर पहुंच गया।मार्केट कैप किसी भी कंपनी के कुल आउटस्टैंडिंग शेयरों की मौजूदा बाजार कीमत को दर्शाता है। इसे कंपनी के कुल जारी शेयरों की संख्या को प्रति शेयर कीमत से गुणा करके निकाला जाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कंपनी के 1 करोड़ शेयर बाजार में हैं और एक शेयर की कीमत 20 रुपये है, तो उसका मार्केट कैप 20 करोड़ रुपये होगा। मार्केट कैप का महत्व केवल कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह निवेशकों के लिए भी बेहद अहम होता है। बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनियां आमतौर पर अधिक स्थिर मानी जाती हैं और उन्हें बाजार से पूंजी जुटाने, ऋण लेने या अन्य कंपनियों के अधिग्रहण में आसानी होती है। दूसरी ओर, छोटे मार्केट कैप वाली कंपनियों में जोखिम अपेक्षाकृत अधिक होता है। निवेशकों के दृष्टिकोण से देखें तो मार्केट कैप में वृद्धि का सीधा लाभ उन्हें मिलता है, क्योंकि इससे उनके निवेश की वैल्यू बढ़ती है। वहीं, गिरावट की स्थिति में निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि TCS का मार्केट कैप बढ़ता है, तो इसके शेयरधारकों की संपत्ति में भी वृद्धि होती है और कंपनी को भविष्य के विस्तार के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होते हैं। कुल मिलाकर, बीते सप्ताह का प्रदर्शन यह दर्शाता है कि भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों का भरोसा बना हुआ है और मजबूत कंपनियों में निवेश का रुझान लगातार बढ़ रहा है।

बंबई उच्च न्यायालय का निर्देश: खाशाबा जाधव को पद्म विभूषण पर 4 मई तक फैसला

बंबई उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता खाशाबा दादासाहेब जाधव को मरणोपरांत पद्म विभूषण देने के मुद्दे पर 4 मई तक निर्णय ले। यह निर्देश न्यायमूर्ति माधव जामदार और न्यायमूर्ति प्रवीण पाटिल की कोल्हापुर पीठ ने 15 अप्रैल को सुनवाई के दौरान दिया। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि महाराष्ट्र के रहने वाले खाशाबा जाधव देश के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता थे। उन्होंने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। उनका निधन वर्ष 1984 में हो गया था, जबकि उन्हें 2001 में मरणोपरांत अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह मामला 'कुश्तीवीर खाशाबा जाधव फाउंडेशन' द्वारा दायर जनहित याचिका के जरिए अदालत में पहुंचा। इस फाउंडेशन की स्थापना जाधव के बेटे रणजीत जाधव ने की है। याचिका में गृह मंत्रालय के पद्म पुरस्कार प्रकोष्ठ को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह जाधव को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित करने के लिए नए सिरे से विचार करे। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जाधव के परिवार ने कई बार सरकार से इस सम्मान के लिए आवेदन किया, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। इसके बाद न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि वह इस मामले में 4 मई तक उचित निर्णय ले और अगली सुनवाई 5 मई को तय की गई है। यह मामला अब खेल जगत और देशभर में चर्चा का विषय बन गया है, जहां कई लोग जाधव को उनके योगदान के अनुरूप सम्मान दिए जाने की मांग कर रहे हैं।

KKR से हार के बाद मैदान पर रो पड़े वैभव सूर्यवंशी

BCCI का बड़ा प्लान
टी20 में दिखेंगी दो टीम इंडिया

भारतीय क्रिकेट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) टी20 प्रारूप में एक साथ दो भारतीय टीमें उतारने की योजना पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बोर्ड 30-35 खिलाड़ियों का एक बड़ा पूल तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे एक ही समय पर अलग-अलग टूर्नामेंट में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व संभव हो सके। इस फैसले के पीछे मुख्य कारण इस साल का व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है। भारत को एक ही समय में एशियाई खेल और भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में हिस्सा लेना है। ऐसे में बीसीसीआई दो अलग-अलग टीमों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रहा है, ताकि दोनों प्रतियोगिताओं में मजबूत प्रदर्शन किया जा सके। रिपोर्ट्स के अनुसार, बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत खिलाड़ियों का एक विस्तृत पूल बनाया जाएगा, जिससे चयनकर्ताओं के पास विकल्पों की कमी न हो। इस पूल में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ-साथ युवा प्रतिभाओं को भी शामिल किया जाएगा। इससे नए खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा, आगामी आयरलैंड दौरा और अन्य सीरीज को ध्यान में रखते हुए भी खिलाड़ियों का रोटेशन प्लान तैयार किया जा रहा है। यह रणनीति टीम के वर्कलोड मैनेजमेंट और खिलाड़ियों की फिटनेस बनाए रखने में भी मदद करेगी। हालांकि, अभी तक इस 30-35 खिलाड़ियों के पूल में किन-किन नामों को शामिल किया जाएगा, इस पर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और मौजूदा फॉर्म के आधार पर चयन होने की संभावना जताई जा रही है।

"अपने देश के लिए नहीं खेलूंगा तो किसी और के लिए भी नहीं" —राशिद

अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग में अपने प्रदर्शन के साथ-साथ अपनी आने वाली किताब को लेकर भी चर्चा में हैं। गुजरात टाइटन्स के लिए खेल रहे राशिद ने अपनी आत्मकथा 'राशिद खान: फ्रॉम स्ट्रीट्स टू स्टारडम' में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिनमें सबसे अहम भारत और ऑस्ट्रेलिया से मिली नागरिकता के प्रस्ताव से जुड़ा है। किताब में राशिद खान ने बताया है कि पिछले कुछ वर्षों में उन्हें भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों की ओर से नागरिकता और उनके लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के प्रस्ताव मिले थे। हालांकि, उन्होंने इन प्रस्तावों को साफ तौर पर ठुकरा दिया। राशिद के अनुसार, आईपीएल 2023 के दौरान उनसे अनौपचारिक रूप से देश बदलने को लेकर संपर्क किया गया था। उन्होंने दावा किया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उनसे बातचीत की और अफगानिस्तान की कठिन परिस्थितियों का हवाला देते हुए भारत में बसने और भारतीय टीम के लिए खेलने का सुझाव दिया। राशिद ने लिखा कि उन्हें यह प्रस्ताव सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने विनम्रता से इसे अस्वीकार कर दिया।राशिद खान ने अपनी किताब में स्पष्ट रूप से कहा, "अगर मैं अपने देश के लिए नहीं खेलूंगा, तो किसी और देश के लिए भी नहीं खेलूंगा।" उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने संबंधित अधिकारी को धन्यवाद देते हुए कहा कि वह अपने देश अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व करना जारी रखेंगे।

अक्षय तृतिया पर अनुष्का शर्मा संग पहुंचे कोहली
प्रेमानंद महाराज से की खास मुलाकात

आईपीएल 2026 के बीच व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर विराट कोहली आध्यात्मिक यात्रा पर वृंदावन पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी मौजूद रहीं। दोनों ने अक्षय तृतिया के पावन अवसर पर वृंदावन स्थित श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में दर्शन किए और संत प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया।इस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विराट कोहली गले में तुलसी की माला पहने नजर आ रहे हैं, जबकि अनुष्का शर्मा सादगी भरे सफेद सूट में दिखाई दे रही हैं। दोनों ने आश्रम में शांत वातावरण के बीच समय बिताया और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने प्रेमानंद महाराज के साथ एकांत में बातचीत भी की, जिसमें जीवन, शांति और आंतरिक संतुलन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। अक्षय तृतिया के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में शामिल होकर इस कपल ने भक्ति भाव से पूजा-अर्चना की। यह पहला मौका नहीं है जब विराट और अनुष्का आध्यात्मिक स्थलों पर पहुंचे हों, लेकिन इस बार उनका यह दौरा खास मायने रखता है क्योंकि यह आईपीएल के बीच हुआ है। क्रिकेट की बात करें तो विराट कोहली इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने 19 रन बनाए थे। अब आरसीबी का अगला मैच 24 अप्रैल को गुजरात टाइटन्स के खिलाफ खेला जाना है। माना जा रहा है कि लगातार मैचों और दबाव भरे माहौल के बीच विराट ने इस छोटे ब्रेक का उपयोग मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन के लिए किया। खेल के साथ-साथ मानसिक मजबूती भी उतनी ही

जरूरी होती है, और यही वजह है कि कई खिलाड़ी समय-समय पर आध्यात्मिकता का सहारा लेते हैं।कुल मिलाकर, विराट और अनुष्का का यह दौरा न सिर्फ उनके व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा है, बल्कि यह दर्शाता है कि व्यस्त पेशेवर जीवन के बीच भी मानसिक संतुलन और शांति के लिए समय निकालना कितना महत्वपूर्ण है।

AI वेटर जीभ-चेहरा देखकर बताएगा- आपको क्या खाना चाहिए?

चीन में AI शेफ ने संभाली रसोई

चीन का AI रोबोट रेस्टोरेंट ग्राहकों के चेहरे और जीभ का विश्लेषण करके उनके लिए खाना सजेस्ट कर रहा है. रोबोटिक 'कर्मचारियों' ने रेस्टोरेंट के मानव कर्मचारियों का वर्कफोर्स 60 प्रतिशत तक कम कर दिया है.

रेस्टोरेंट में एआई रोबोट कस्टमर को स्कैन कर उनके जरूरत के हिसाब से बनाएगा खाना (Photo - Pexels)

पूर्वी चीन के कई रेस्टोरेंट कॉस्ट कटिंग के लिए और 100 से अधिक डिश पकाने के लिए AI रोबोट का इस्तेमाल कर रहे हैं. इससे सोशल मीडिया पर गरमागरम बहस छिड़ गई है. झेजियांग टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, झेजियांग प्रांत के हांगझोऊ में कम से कम तीन ऐसे रेस्टोरेंट महीनों से चल रहे हैं. इनमें से एक, शिहू जिले में स्थित 24 जिएकी रोबोट रेस्टोरेंट, आठ रोबोटों का इस्तेमाल करता है. ये रोबोट ऑर्डर लेने, खाना परोसने, सफाई करने और खाना पकाने का काम संभालते हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि इन रोबोटों ने रसोई कर्मचारियों के कुल कार्यभार का 60 प्रतिशत हिस्सा साझा किया है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक,कस्टमर के ऑर्डर देने से पहले, रोबोट उनके चेहरे और जीभ को स्कैन करके और उनसे कुछ सरल सवाल करते हैं. इनका जवाब देने के बाद इसका 'एआई विश्लेषण' किया जाता है. इसके बाद रोबोट ग्राहक की लाइफस्टाइल, भावनाओं और डायजेस्टिव सिस्टम की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और फिर मौसम के अनुसार कस्टमर के लिए हेल्दी फूड सजेस्ट करते हैं. ⊙

महिला ने बालकनी से उड़ाए डेढ़ करोड़ रूपये

इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक महिला अपने घर के बालकनी से नोट उड़ाते दिखाई दे रही है. यह वीडियो चीन का बताया जा रहा है. दावा किया गया है कि महिला ने बालकनी में खड़े होकर लगभग 162,247 डॉलर कैश हवा में उड़ा दिए. डेली मेल के इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर किया गया है. इसमें बताया गया है कि चीन के ग्वांगडोंग में एक महिला ने अपने आलीशान अपार्टमेंट से लगभग 162,247 डॉलर कैश यानी करीबन डेढ़ करोड़ रूपये उड़ा दिए. ⊙

इंजीनियर बोला, एक गलती ने 4 साल पीछे धकेला करियर

कंपनी से वफादारी नहीं बढ़ाती आपकी सैलरी

आज के समय में लोग करियर में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कई बार कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमारी ग्रोथ को धीमा कर देते हैं.

हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के एक टेक्निकल एक्सपर्ट ने अपनी ऐसी ही एक गलती के बारे में बताया, जिसने उनकी सैलरी बढ़ने में 4 साल की देरी कर दी. इस इंजीनियर का नाम शैलेश गुरुंग है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों का अनुभव बताया. शैलेश ने अपने करियर की शुरुआत टाटा कंसल्टेंसी

सर्विसेज यानी TCS से की थी. उन्होंने वहां करीब 4 साल तक काम किया. इस दौरान उन्होंने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया. उन्हें उम्मीद थी कि समय के साथ उनकी सैलरी और ग्रोथ भी तेजी से बढ़ेगी. ⊙

TCS के बाद चर्चा में लेंसकार्ट का ड्रेस कोड

बिंदी-तिलक की मनाही, हिजाब को परमिशन

इन दिनों TCS के नासिक ऑफिस में एचार पॉलिसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. वहां की एचआर हेड पर कर्मचारियों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने और दबाव डालने जैसे आरोप लग रहे हैं. इसी बीच लेंसकार्ट से जुड़ी एक ड्रेसकोड पॉलिसी का डॉक्यूमेंट लीक हो गया. हालांकि, इस पर लेंसकार्ट के फाउंडर की सफाई भी आई है.

ऐसे में समझते हैं यह पूरा मामला क्या है. TCS के बाद अब लेंसकार्ट को अपनी ग्रूमिंग गाइड को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. क्योंकि कंपनी के ड्रेसकोड पॉलिसी से जुड़े एक लीक डॉक्यूमेंट की कुछ बातों ने लोगों का ध्यान खींचा है. इस लीक डॉक्यूमेंट के मुताबिक,

यह आईवियर स्टार्टअप अपने वर्कप्लेस पर कर्मचारियों को हिजाब पहनने की अनुमति देता है, लेकिन बिंदी, तिलक और कलावा पहनना बैन करता है.

लेंस्कार्ट ऑफिस के ड्रेस कोड संबंधी गाइडलाइन से जुड़ा एक डॉक्युमेंट लीक होने से भारी विवाद खड़ा हो गया है. क्योंकि लोगों ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि इसमें वर्क प्लेस पर बिंदी और तिलक लगाने की अनुमति नहीं है, जबकि हिजाब की परमिशन है.

इस पर लेंसकार्ट के संस्थापक और सीईओ पीयूष बंसल ने स्पष्ट किया कि कंपनी की नीतियों में बदलाव आया है और यह डॉक्यूमेंट उनके वर्तमान गाइडलाइन को नहीं दिखाती है. विवाद बढ़ने पर, लेंस्कार्ट के संस्थापक और सीईओ पीयूष बंसल ने स्पष्ट किया कि नीतिगत दस्तावेज़ गलत था. ⊙

शोहरत के पीछे छिपा दर्द, अंदर से टूट चुकी थीं सिंगर

जैस्मिन सैंडलस का बड़ा खुलासा: शराब की लत से जंग की दर्दनाक कहानी

3000 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर सुर्खियों में आई फिल्म धुरंधर: द रिवेंज इन दिनों सिर्फ अपनी सफलता ही नहीं, बल्कि उससे जुड़े कलाकारों के व्यक्तिगत खुलासों के कारण भी चर्चा में है। फिल्म के लोकप्रिय गीत 'जाइए सजना' को अपनी आवाज देने वाली सिंगर जैस्मिन सैंडलस ने हाल ही में अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जैस्मिन सैंडलस ने रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट में खुलकर बताया कि कैसे वह सफलता के शिखर पर होने के बावजूद अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थीं। उन्होंने स्वीकार किया कि 23 साल की उम्र में उन्होंने शराब पीना शुरू किया, जो धीरे-धीरे उनकी लत बन गई। उनके अनुसार, जीवन की भावनात्मक चुनौतियों और व्यक्तिगत संघर्षों ने उन्हें इस रास्ते पर धकेला।उन्होंने कहा कि वह समय उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था, जब एक तरफ वह अपने करियर में सफलता हासिल कर रही थीं, वहीं दूसरी ओर निजी जीवन में कई समस्याओं से जूझ रही थीं। परिवार में रिश्तों का टूटना, पिता का निधन और अंदरूनी अकेलापन उन्हें लगातार परेशान कर रहा था। उन्होंने माना कि उस दौरान उन्होंने जरूरत से ज्यादा शराब का सेवन किया, जिसका उन्हें आज भी पछतावा है। जैस्मिन ने अपने बचपन की तकलीफों का जिक्र करते हुए बताया कि उनके माता-पिता के साथ संबंधों में आई दरारों ने उनके मन पर गहरा असर छोड़ा। उन्होंने कहा कि बचपन में मिली भावनात्मक चोटें आज तक पूरी तरह नहीं भर पाई हैं। यही वजह रही कि वह हमेशा एक "सुरक्षित जगह" या अपनापन तलाशती रहीं, लेकिन यह तलाश उन्हें गलत रास्ते पर ले गई।उन्होंने अपने अकेलेपन के बारे में भी खुलकर बात की। जैस्मिन ने बताया कि बाहर से उनकी जिंदगी बेहद ग्लैमरस और खुशहाल दिखती थी, लेकिन अंदर से वह बेहद अकेली महसूस करती थीं। भीड़ के बीच भी वह खुद को अलग-थलग पाती थीं और समझ नहीं पाती थीं कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकलें। हालांकि, इस कठिन दौर से उबरने में उनके परिवार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खासकर उनकी मां ने हर मुश्किल समय में उनका साथ दिया और उन्हें संभाला। जैस्मिन ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से थी, लेकिन परिवार के प्यार और समर्थन ने उन्हें दोबारा खड़ा होने की ताकत दी। उन्होंने यह भी बताया कि पुरानी आदतों से बाहर निकलना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और खुद को एक और मौका देने की कोशिश की। धीरे-धीरे उन्होंने अपनी जिंदगी से नकारात्मक चीजों को दूर किया और एक नई शुरुआत की। काम के मोर्चे पर, जैस्मिन सैंडलस लगातार सक्रिय हैं। 'जाइए सजना' के अलावा उन्होंने फिल्म के अन्य गीतों में भी अपनी आवाज दी है और कई लाइव कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म कर रही हैं। उनकी यह कहानी न केवल उनके संघर्ष को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि मजबूत इच्छाशक्ति और परिवार के सहयोग से किसी भी मुश्किल से बाहर निकला जा सकता है।

राहुल गांधी केस में बड़ा मोड़

जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने खुद को किया अलग

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में राहुल गांधी की नागरिकता मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने याचिकाकर्ता के विवादित सोशल मीडिया पोस्ट पर नाराज होकर खुद को केस से अलग कर लिया। कोर्ट ने कहा कि पोस्ट से न्यायपालिका की छवि प्रभावित हुई है।

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने स्वयं को इस केस से अलग (recuse) कर लिया। यह फैसला याचिकाकर्ता द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए आपत्तिजनक पोस्टों के बाद लिया गया। दरअसल, कर्नाटक निवासी भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी पर भारतीय के साथ-साथ ब्रिटिश नागरिकता रखने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। पहले यह याचिका एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अपील की।17 अप्रैल को जस्टिस विद्यार्थी ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। हालांकि, अगले ही दिन उन्होंने अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि बिना राहुल गांधी को नोटिस जारी किए ऐसा आदेश देना उचित नहीं है। इसी बीच, 18 अप्रैल को याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दो विवादित पोस्ट किए। पहली पोस्ट में उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मामले की स्थिति में कोई बदलाव होता है तो वे "माफिया, अंडरवर्ल्ड और अवैध गठजोड़ों" का पर्दाफाश करेंगे। दूसरी पोस्ट में उन्होंने कथित रूप से रिश्वत लेने का संकेत देते हुए कहा कि "यदि पैसा वापस नहीं किया गया तो इंटरसेप्ट की गई कॉल सार्वजनिक कर दी जाएगी।" हालांकि, इन पोस्टों में किसी व्यक्ति या जज का नाम नहीं लिया गया था।सोमवार को जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, जस्टिस विद्यार्थी ने इन पोस्टों पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि "पीठ पीछे कीचड़ उछालना कैसे उचित है?" और कहा कि अदालत के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। जज ने यह भी टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता ने "राजनीतिक लाभ के लिए अदालत का इस्तेमाल किया है।"कोर्ट रूम में हुई बहस के दौरान शिशिर ने अपनी सफाई में कहा कि उनके पोस्ट अदालत के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए थे जो उन पर दबाव बना रहे थे। हालांकि, अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसे बयान अदालत की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं।सरकारी वकील और डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने भी याचिकाकर्ता के पोस्ट का बचाव करने से इनकार किया और कहा कि किसी को भी हाईकोर्ट पर इस तरह सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। इन घटनाओं के बाद जस्टिस विद्यार्थी ने स्वयं को मामले से अलग कर लिया और कहा कि अब इस केस की सुनवाई किसी अन्य बेंच द्वारा की जाएगी।गौरतलब है कि इससे पहले 2019 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी इसी प्रकार की याचिका को खारिज कर दिया था। उस समय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि किसी कंपनी के दस्तावेज में नाम दर्ज होने मात्र से नागरिकता निर्धारित नहीं होती। फिलहाल, यह मामला न्यायिक और राजनीतिक दोनों दृष्टिकोण से चर्चा में बना हुआ है और आगे की सुनवाई नई बेंच के समक्ष होगी।

लखनऊ के शहीद पथ पर बड़ा सड़क हादसा, लोडर ट्रक से टकराया

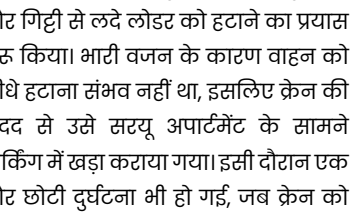

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ में देर रात एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया, जहां शहीद पथ पर एक लोडर ट्रक के पीछे जा घुसा। टक्कर इतनी तेज थी कि लोडर का केबिन बुरी तरह पिचक गया और उसमें ड्राइवर फंस गया। यह घटना थाना गोमतीनगर विस्तार थाना क्षेत्र में पेनेशिया हॉस्पिटल के पास करीब रात 2:15 बजे हुई। बताया जा रहा है कि गिट्टी से लदा लोडर आगे चल रहे ट्रक से टकरा गया, जिससे ड्राइवर केबिन के अंदर ही फंस गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए ड्रिल मशीन से केबिन को काटकर ड्राइवर को बाहर निकाला। घायल को एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।घायल ड्राइवर की पहचान बस्ती जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी 24 वर्षीय विकास पुत्र जीत बहादुर के रूप में हुई है। हादसे में उसके पैर में गंभीर चोट आई है। मौके पर मौजूद उसके साथी रवि विश्वनाथ ने भी राहत कार्य में मदद की।हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। ट्रैफिक को बहाल करने के लिए पुलिस ने क्रेन बुलवाई और गिट्टी से लदे लोडर को हटाने का प्रयास शुरू किया। भारी वजन के कारण वाहन को सीधे हटाना संभव नहीं था, इसलिए क्रेन की मदद से उसे सरयू अपार्टमेंट के सामने पार्किंग में खड़ा कराया गया। इसी दौरान एक और छोटी दुर्घटना भी हो गई, जब क्रेन को पीछे से आ रही बस ने टक्कर मार दी। हालांकि, इस घटना में किसी तरह की जनहानि या बड़ा नुकसान नहीं हुआ। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

पोस्टमॉर्टम के लिए घंटों इंतजार सिस्टम की सुस्ती उजागर

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ में पोस्टमॉर्टम प्रक्रिया में हो रही देरी आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है। कई मामलों में परिजनों को घंटों ही नहीं, बल्कि पूरा दिन इंतजार करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में नई मॉर्चरी बनाई गई थी, जिसे वर्ष 2024 में हैंडओवर भी कर दिया गया, लेकिन दो साल बाद भी यह अब तक चालू नहीं हो सकी है।जानकारी के अनुसार, नई मॉर्चरी को शुरू करने के लिए कम से कम 15 कर्मचारियों की जरूरत है, जिनमें फॉरेंसिक विशेषज्ञ, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और वीडियोग्राफर शामिल हैं। इसके अलावा आवश्यक उपकरणों की भी कमी है। मार्च में स्वास्थ्य महानिदेशक की ओर से निर्देश जारी किए गए थे कि प्रदेश के सभी पोस्टमॉर्टम हाउस में सुविधाएं जल्द सुनिश्चित की जाएं, लेकिन लखनऊ में इसका असर नहीं दिख रहा।वर्तमान में पुराने पोस्टमॉर्टम हाउस में केवल 12 कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि हर शिफ्ट में कम से कम चार कर्मचारियों की जरूरत होती है। कई बार अन्य कार्यों में स्टाफ लगाए जाने के कारण पोस्टमॉर्टम में और देरी हो जाती है। ऐसे में शवों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, जिससे परिजनों की परेशानी बढ़ जाती है। नई मॉर्चरी शुरू होने पर बड़ी राहत मिल सकती है। मौजूदा व्यवस्था में जहां केवल 6 पोस्टमॉर्टम प्लेटफॉर्म हैं, वहीं नई सुविधा के शुरू होने के बाद 12 और प्लेटफॉर्म जुड़ जाएंगे। इससे कुल 18 शवों का एक साथ पोस्टमॉर्टम संभव

होगा और लंबित मामलों में तेजी आएगी। हालांकि, इस देरी के पीछे प्रशासनिक कारण भी सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय और केजीएमयू प्रशासन के बीच समन्वय की कमी के चलते काम अटका हुआ है। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, लेकिन मैनपावर की व्यवस्था अब तक नहीं हो सकी है। नवंबर 2025 में भी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के आदेश जारी हुए थे, लेकिन पांच महीने बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। इससे साफ है कि नई मॉर्चरी फिलहाल कागजों तक ही सीमित है, जबकि आम जनता को अब भी राहत का इंतजार है।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर के घर 10 लाख की चोरी

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ के काकोरी क्षेत्र में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां मौंदा गांव में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के सूने घर को निशाना बनाकर चोर लाखों रुपये का सामान लेकर फरार हो गए। घटना उस समय हुई जब परिवार घर पर मौजूद नहीं था। पीड़ित राजपाल यादव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं और बीते शुक्रवार को अपने परिवार के साथ मध्य प्रदेश के मैहर में माता के दर्शन के लिए गए थे। करीब तीन दिन तक घर खाली पड़ा रहा, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया।रविवार रात जब परिवार वापस लौटा, तो घर का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ मिला और अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। चोरों ने अलमारियां और बक्से तोड़कर लगभग 30 हजार रुपये नकद और करीब 10 लाख रुपये के जेवरात चोरी कर लिए। चोरी हुए सामान में सोने-चांदी के गहने

जैसे झाला, झुमकी, चेन और पायल शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाले हैं और वर्तमान में लखनऊ में रहकर नौकरी कर रहे हैं। इस घटना ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।

लखनऊ में भीषण गर्मी का कहर, तापमान 41°C पार

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भीषण गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। सोमवार सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान कर दिया। सुबह के समय हल्की पछुआ हवाएं चलीं, लेकिन इनसे राहत मिलने के बजाय गर्मी और बढ़ गई। दोपहर 12:30 बजे तक शहर का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया। तेज धूप के कारण आमजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पैदल चलने वाले लोग छाता, गमछा और सिर ढककर ही बाहर निकलते नजर आए। दोपहर के समय स्कूलों की छुट्टी होने पर घर लौट रहे बच्चे भी गर्मी से बेहाल दिखे। 1090 चौराहे पर एक छात्र ने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि इस तेज धूप और लू के बीच बिना जरूरी काम के बाहर न निकलें और लगातार पानी पीते रहें, ताकि शरीर हाइड्रेटेड बना रहे। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं, रविवार को अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.4 डिग्री अधिक था। न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.8 डिग्री ज्यादा था।लगातार बढ़ती गर्मी और लू के चलते स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं।

एलयू कैंपस में छात्र संगठनों का हंगामा, बढ़ी फीस पर विरोध

लखनऊ विश्वविद्यालय में सोमवार को छात्रों का विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया, जब विभिन्न छात्र संगठनों ने बुनियादी सुविधाओं की कमी और फीस वृद्धि के विरोध में कुलपति कार्यालय का घेराव किया। स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब कुछ छात्र जबरन वीसी ऑफिस में घुसने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई। दोपहर करीब 12 बजे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों ने कुलपति प्रोफेसर जय प्रकाश सैनी के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में फ्रीजर, वाटर कूलर और एयर कंडीशनर खराब हैं, जिससे भीषण गर्मी में उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों का यह भी दावा था कि पीने के पानी की गुणवत्ता बेहद खराब है और उसका टीडीएस स्तर 500 तक पहुंच गया है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है।इसके बाद करीब 2 बजे समाजवादी छात्र सभा के छात्र भी प्रदर्शन में शामिल हो गए। उन्होंने फीस वृद्धि और खराब सुविधाओं को लेकर विरोध जताया। छात्रों का कहना था कि उन्हें कुलपति से मिलने नहीं दिया गया और कार्यालय के बाहर ताला लगा दिया गया, जिससे उनकी नाराजगी और बढ़ गई।करीब 3 बजे नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। NSUI अध्यक्ष सुधांशु राणा के नेतृत्व में छात्रों ने नारेबाजी की और परिसर में पोस्टर लगाए। सभी संगठनों ने एक सुर में विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्रों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में हॉस्टल, कैंटीन और लाइब्रेरी जैसी मूलभूत सुविधाएं बदहाल हैं। भीषण गर्मी के बावजूद कहीं भी एसी की व्यवस्था नहीं है और खराब पानी के कारण छात्र बीमार पड़ रहे हैं। छात्रों ने फीस में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का भी विरोध किया और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की,

लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे। विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों ने भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शन देर तक जारी रहा।छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस घटना ने विश्वविद्यालय में प्रशासन और छात्रों के बीच बढ़ते तनाव को उजागर कर दिया है।

जिले भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया भगवान परशुराम जन्मोत्सव

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष अशोक बाजपेई वेदांती ने कहा कि सदर विधायक ने मंदिर बनवाकर प्रशंसनीय कार्य किया है। अन्य ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष धर्मेश दीक्षित, ज्ञानेश द्विवेदी आदि ने भी इसकी सराहना की। कार्यक्रम में मनोज द्विवेदी, विजय त्रिपाठी, मोना पांडेय, अमित शुक्ला, गोपाल अवस्थी, व्यापार मंडल अध्यक्ष अमित मिश्रा व अखिलेश अवस्थी ने विधायक व उनके बेटे प्रखर गुप्ता को सम्मानित किया। आचार्यों में सागर तिवारी व ओमी मिश्रा आदि ने घंटा भेंट किया। कार्यक्रम में पूर्व एमएलसी अरविंद त्रिपाठी, भाजपा जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी, पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद अवस्थी, प्रभाशंकर दीक्षित, आशादीन तिवारी, हरिहर दीक्षित, धर्मेंद्र दीक्षित, विमल द्विवेदी, ब्रजेश पांडेय आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय सवर्ण एकता मंच ने कल्याणी देवी मंदिर पर परशुराम जन्मोत्सव मनाया गया। संस्था के मुख्य संरक्षक डॉ. मनोज श्रीवास्तव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमानिवास वाजपेई व प्रदेश अध्यक्ष सुशील शुक्ला ने कहा कि भगवान परशुराम का जीवन हमें अन्याय के विरुद्ध खड़े होने और समाज में समानता एवं सद्भाव बनाए रखने की सीख देता है। डॉ. विनय शंकर दीक्षित, पवन निगम, प्रेम सिंह सेंगर, प्रभात सिन्हा, योगेंद्र प्रताप सिंह, अखिलेश ओमर, डॉ. आरके श्रीवास्तव, मधुसूदन शुक्ला, सोमनाथ तिवारी, राकेश तिवारी, राहुल राम द्विवेदी आदि

मौजूद रहे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के ओम प्रकाश मिश्रा, बृजेश कुमार पांडेय, मूलचंद्र शुक्ला, लक्ष्मीकांत पांडेय आदि ने मोतीनगर में जन्मोत्सव मनाया। सर्व सनातन उत्थान सेवा समिति की जिला इकाई ने भी जन्मोत्सव मनाया। ग्राम मंगतखेड़ा में प्रधान मनोज द्विवेदी, किसान उत्थान सेवा समिति के अध्यक्ष अजय पांडे, पुरवा अध्यक्ष अर्पित पांडे एवं जिला महामंत्री पवन तिवारी आदि मौजूद रहे। सर्व सनातन उत्थान सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश शुक्ला ने मंगतखेड़ा में भगवान परशुराम मंदिर बनाए जाने की बात कही। नव युवा ब्राह्मण कल्याण महासभा ने कलक्टरगंज फाटक के अंदर स्थित शिव मंदिर में परशुराम जन्मोत्सव मनाया। अनुराग त्रिपाठी, पं. मनोज कुमार त्रिवेदी, प्रवीण मिश्रा, मोनू दीक्षित, आशुतोष तिवारी, देवेंद्र बाजपेयी आदि मौजूद रहे। नवाबगंज। विकासखंड के ग्राम भितरेपार में भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन हुआ। पूर्व एमएलसी अरविंद त्रिपाठी ने समाज को एकजुट करने का आह्वान किया। आयोजक ज्ञानेंद्र पाठक, कृष्णदत्त त्रिपाठी, अमित मिश्रा, आशीष, नीटू बाजपेई, नृपेंद्र द्विवेदी, व्योमजी द्विवेदी, विनोद कुमार तिवारी, श्रीकृष्ण शुक्ला और शैलेंद्र शुक्ला आदि मौजूद रहे। या। क्षेत्र के ग्राम पड़रीकला बाजार स्थित ढकलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान परशुराम का पूजन-अर्चन किया गया। आयोजक जबरेला के प्रमोद कुमार बाजपेई व कैलाश नाथ बाजपेयी ने 101 ब्राह्मणों को भगवान परशुराम की प्रतिमा एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। समापन प्रसाद वितरण के साथ हुआ। आशुतोष बाजपेयी, राजा बाजपेयी, आदित्य दीक्षित, ब्रजेश मिश्रा, वीरेंद्र पांडेय, दीपू तिवारी, उमानाथ मिश्रा, गुड्डू तिवारी, शिव नारायण बाजपेई आदि मौजूद रहे।

कल्याणी नदी पुल से आवागमन बंद

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

काली मिट्टी-शिवराजपुर मार्ग पर कस्बे में कल्याणी नदी पर बने 51 साल पुराने पुल के ज्वाइंट की मरम्मत का कार्य पूरा हो गया है। अब बेयरिंग बदलने का काम सोमवार से शुरू होगा। इसके लिए रूट डायवर्जन प्लान तैयार कर लिया गया है, इसे रात से लागू हो जाएगा। सात दिन तक आवागमन पर रोक रहेगी। इस दौरान हल्के वाहन फतेहपुर चौरासी से होते हुए पिथनहारा संपर्क मार्ग से निकाले जाएंगे।

कस्बा फतेहपुर चौरासी के पास कल्याणी नदी के पुल का निर्माण वर्ष 1975 में हुआ था। कानपुर से शिवराजपुर जाने के लिए इसी पुल से आवागमन करते हैं। वर्तमान में पुल के ऊपरी हिस्से के ज्वाइंट खुल गए थे। नीचे बेयरिंग भी पुरानी हो गई थीं। इसके लिए शासन से पीडब्ल्यूडी ने बजट की मांग की थी। इसके लिए करीब 39 लाख स्वीकृत हुए हैं। 30 मार्च से पीडब्ल्यूडी ने काम शुरू कराया था। पहले ज्वाइंट की मरम्मत शुरू कराई गई थी। ज्वाइंट मरम्मत में रोड के आधी तरफ से यातायात निकाला जाता रहा। ज्वाइंट वाले स्थान पर खोदाई करके नए सिरे से मरम्मत की गई है। सोमवार से बेयरिंग बदलने का काम किया जाना है। इसके लिए रविवार शाम को इंजीनियरों ने बेयरिंग बदलने की तैयारियां पूरी कर लीं।एक्सईएन सुबोध कुमार ने बताया कि बेयरिंग बदलने के दौरान यातायात डायवर्ट किया जाएगा। बताया कि हल्के वाहन फतेहपुर चौरासी आबादी से दाहिनी ओर पिथनहारा संपर्क मार्ग होते हुए निकाले जाएंगे।

लखनऊ रैली को लेकर उन्नाव में BJP की तैयारी तेज

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

राजधानी लखनऊ में मंगलवार को प्रस्तावित "महिला जन आक्रोश रैली एवं मार्च पास्ट" को लेकर उन्नाव में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सोमवार को भाजपा जिला कार्यालय में एक तैयारी बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने रैली को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। इस बैठक में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा गया। प्रदेश उपाध्यक्ष मानवेन्द्र सिंह ने बैठक में कहा कि विपक्ष का दोहरा चरित्र देश के सामने आ चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने लोकसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को पारित नहीं होने दिया। इससे देश की आधी आबादी को उनके अधिकार से वंचित रखा गया। उन्होंने कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी पर महिलाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। प्रदेश मंत्री एवं जिला प्रभारी अर्चना मिश्रा ने कहा कि विपक्ष परिवारवाद की राजनीति में उलझा हुआ है। उन्हें डर है कि महिलाओं के सशक्त होने से उनका वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि लखनऊ में होने वाली यह रैली ऐसे सुधार विरोधी चेहरों को उजागर करेगी और नारी शक्ति की ताकत का प्रदर्शन करेगी। भाजपा जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी ने बताया कि उन्नाव की मातृशक्ति इस रैली में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेगी और इसे ऐतिहासिक बनाएगी। उन्होंने दावा किया कि महिलाओं की एकजुटता विपक्ष के हर षड्यंत्र का करारा जवाब देगी। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह, सदर विधायक पंकज गुप्ता, विधायक बम्बा लाल दिवाकर, विधायक आशुतोष शुक्ला, विधायक अनिल सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख संध्या पटेल सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त, जिला उपाध्यक्ष विमला कुरील और किरण सिंह, जिला महामंत्री प्रवीण सिंह नूतन, रजनीश वर्मा, मनीष जायसवाल, तथा जिला मंत्री साधना दीक्षित सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी भी मौजूद थे।

साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एक बड़े मेट्रोमोनियल फ्रॉड का पर्दाफाश किया

उन्नाव साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एक बड़े मेट्रोमोनियल फ्रॉड का पर्दाफाश किया है। पुलिस टीम ने ठगी की शिकार एक महिला के खाते में 35,11,101 रुपये की राशि वापस कराई है। यह कार्रवाई एसएसपी के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी व क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम के पर्यवेक्षण में की गई। यह मामला सिविल लाइंस निवासी श्रीमती विनीता द्विवेदी से संबंधित है। उन्होंने 17 जनवरी 2026 को साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि ठगों ने मेट्रोमोनियल वेबसाइट के जरिए शादी का झांसा देकर उनसे अलग-अलग बहानों और रीति-रिवाजों के नाम पर कुल 75,11,353 रुपये ट्रांसफर करा लिए थे। शुरुआत में विनीता द्विवेदी को इस धोखाधड़ी का अंदाजा नहीं हुआ। लगभग 45 दिन बाद जब उन्हें सच्चाई का पता चला, तो उन्होंने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। प्राप्त तहरीर के आधार पर साइबर क्राइम थाना उन्नाव में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। जांच के दौरान संबंधित बैंक खातों को फ्रीज कराया गया और बैंक अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर धनराशि की रिकवरी प्रक्रिया तेज की गई। कड़ी मेहनत और तकनीकी विश्लेषण के जरिए पुलिस टीम ने ठगी की रकम में से 35,11,101 रुपये पीड़िता के खाते में वापस कराए।

अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला

चायवाले के मुद्दे पर सरकार को घेरा, PDA जोर

फतेहपुर में चायवाले पर कार्रवाई को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इसे गरीबों का उत्पीड़न बताया और PDA एकता की बात कही।

यूपी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। फतेहपुर में एक गरीब चायवाले पर एल्युमीनियम के बर्तन इस्तेमाल करने के आरोप में छापेमारी का मामला उठाते हुए उन्होंने इसे राजनीतिक प्रताड़ना बताया। फतेहपुर में जिस चाय की दुकान पर छापेमारी की गई थी, उस चायवाले को अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित सपा पार्टी कार्यालय बुलाया। वहाँ उन्होंने चायवाले को पीतल का भगोना गिफ्ट किया। अखिलेश ने कहा कि सरकार गरीब चायवाले को परेशान कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने सवाल किया कि क्या दुनिया के बड़े ब्रांड के बर्तन और कुकर बेचने या घरों में रखने पर भी छापेमारी होगी? उन्होंने एक्स पर लिखा कि एक गरीब चायवाले को सिर्फ एल्युमीनियम का बर्तन इस्तेमाल करने पर सरकारी विभाग और भाजपाइयों के गुर्गे प्रताड़ित कर रहे हैं। अखिलेश ने व्यंग्य करते हुए लिखा कि ये भी दिखवा लीजिए कि जब आपके यहाँ खिचड़ी बनती है तो उसका बर्तन कहीं एल्युमीनियम का तो नहीं है? या फिर उसे भी सोने में ढलवा लिया है? उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार जब भी किसी की रोजी-रोटी छीनने की कोशिश करेगी, तब सपा अपनी पूरी ताकत से उसकी मदद करेगी। अखिलेश यादव ने जोर देकर कहा कि वर्चस्ववादी भाजपा की क्रूरता का जवाब पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की एकता से दिया जाएगा। उन्होंने पूछा कि 5 बड़ा या 95? उन्होंने लिखा कि अब पीडीए साथ-साथ बढ़ेगा और पीडीए ही पीडीए की ताकत बनेगा। अखिलेश का आरोप है कि भाजपा और उसके साथी 2024 के चुनावी पराजय को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें डर है कि देश की 95% आबादी से बना पीडीए जब एकजुट होकर खड़ा होगा, तो भाजपा का क्या होगा। अखिलेश ने भाजपा पर पुराने आरोप दोहराते हुए कहा कि ये लोग आजादी से पहले भी देश से गद्दारी करते थे, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ मुखबिरी करते थे। उन्होंने भाजपा को "विषग्रंथी" बताया और कहा कि ये लोग देश को धोखा देकर अकूत दौलत इकट्ठा करते रहे हैं। उन्होंने भाजपा की मानसिकता को "घृणित" और "विषैली" बताया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के आधिकारिक हैंडल से जो अपमानजनक पोस्ट की गई, वो राजनीतिक नैतिक पतन का दस्तावेज है। अखिलेश का कहना है कि भाजपा ने पीडीए समाज के साथ एक लकीर खींच दी है। अब भाजपा में शामिल पीडीए समाज के सांसद, विधायक और कार्यकर्ताओं का राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया है। पीडीए समाज उन्हें हमेशा के लिए अस्वीकार कर देगा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के अंदर भ्रष्टाचार और आपसी लड़ाई बढ़ रही है। जल्द ही ये लोग खुद-ब-खुद टूट जाएंगे। अखिलेश ने समर्थकों से अपील की कि पीडीए की एकता को और मजबूत करें। उन्होंने कहा कि जब-जब पीडीए का अपमान होता है, तब उसकी एकजुटता और मजबूत हो जाती है।

वाराणसी के प्रमुख घाटों पर डिजिटल लैगेज लॉकर्स की सुविधा शुरू करने की योजना

काशी में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए जिला प्रशासन ने एक नई पहल की है। बताया जा रहा कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन और गंगा स्नान के दौरान सामानों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाए जा रहा है। जिला प्रशासन ने से काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके आसपास के प्रमुख घाटों पर डिजिटल लैगेज लॉकर्स की सुविधा शुरू करने की योजना बनाई है। इस कदम से लोग अपने सामानों को लॉकर में रखकर निश्चित होकर स्नान और दर्शन कर पाएंगे। शहर के प्रमुख स्थान दशाश्वमेध प्लाजा, गोदौलिया, टाउन हॉल और बेनिया पार्किंग में इसे लगाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। नगर निगम के मुताबिक, यहां दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिलेगा और इस लॉकर में सूटकेस के साथ अन्य जरूरी सामान भी रख सकते हैं। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि प्राथमिक चरण में योजना के तहत 225 डिजिटल लॉकर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सभी लॉकर अलग-अलग आकार के होंगे। छोटा, मध्यम, बड़ा और एक्स्ट्रा लार्ज। उन्होंने बताया कि छोटे लॉकर में मोबाइल वा पर्श जैसे छोटे सामान रखे जा सकते हैं, जबकि बड़े और एक्स्ट्रा लार्ज लॉकर में बैग और अधिकतम दो सूटकेस रखने तक की सुविधा होगी। इन डिजिटल लॉकर के इस्तेमाल के लिए डिजिटल पेमेंट यानी ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा प्रदान की जाएगी। श्रद्धालु बारकोड के जरिए ऑनलाइन भुगतान कर लॉकर का उपयोग कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इसके पीछे का मकसद इसकी पारदर्शिता को बढ़ाना और कैश लेनदेन की झंझट को खत्म करना है। दरअसल, काशी दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है और इस कदम से प्राचीन शहर को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने का एक उदाहरण भी साबित होगा। बता दें कि काशी में प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिनके लिए यह सुविधा वरदान साबित हो सकती है। वहीं, त्योहार और विशेष अवसरों पर इसका इस्तेमाल कहीं ज्यादा हो सकता है।

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की

बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मौलाना रजवी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद है और इसे कलंक कहना सरासर गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मस्जिद के नाम पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता और कयामत तक उस पर भगवा झंडा नहीं लहराया जा सकता। मौलाना ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री को बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को न उकसाएं और न भड़काएं। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी का मामला अदालत में विचाराधीन है, जहां हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। अदालत का जो भी फैसला होगा, वह सभी पक्षों को मान्य होगा। मौलाना रजवी ने आरोप लगाया कि इस तरह की बयानबाजी मुकदमे को प्रभावित करने के लिए की जा रही है। उन्होंने अदालत से स्वत: संज्ञान लेकर धीरेंद्र शास्त्री को तलब करने की मांग की, ताकि उनसे भड़काऊ बयान देने का कारण पूछा जा सके। मौलाना ने शरीयत का नजरिया स्पष्ट करते हुए कहा कि कोई भी मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। शरीयत किसी भी मुसलमान को इसकी इजाजत नहीं देती है। उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री के दावों को झूठा करार दिया। मौलाना रजवी ने जोर देकर कहा कि ज्ञानवापी से जुड़ा मामला अभी अदालत में चल रहा है। रोजाना सुनवाई हो रही है और दोनों पक्ष अपनी दलीलें रख रहे हैं। उन्होंने पंडित धीरेंद्र शास्त्री को चेतावनी दी कि वे बहुसंख्यक समुदाय को भड़काने वाले बयान न दें। अदालत का फैसला ही अंतिम और सर्वमान्य होगा।

आजम खान और अब्दुल्ला आजम की सजा घटाने की अपील खारिजपहले से तय सात साल की सजा बरकरार

दो पैन कार्ड मामले में सजा काट रहे सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को राहत नहीं मिली है। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने सोमवार को सजा कम करने की उनकी अपील खारिज कर दी। मामले में पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ बचाव पक्ष ने सजा कम करने की अपील की थी, जबकि अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सजा में कोई राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट के इस निर्णय के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम की सजा यथावत बनी रहेगी।